



प्रीलिमिंस फैक्ट्स :19 सतिंबर

अखलि भारतीय पेंशन अदालत (All India Pension Adalat)

- भारत सरकार के कार्मिक, लोक शकियात एवं पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण वभिण द्वारा कयि 'पेंशन अदालत' की शुरुआत की गई।
- इसके साथ वभिणों के लयि संस्थागत स्मृतिको संयोजति करने के कार्म में उल्लेखनीय योगदान देने के लयि 6 पेंशनभोगियों को 'अनुभव' पुरस्कार, 2018 से भी सम्मानति कयि गया।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आव्हान पर वर्ष 2015 में 'अनुभव योजना' की शुरुआत की गई थी।
- इसके माध्यम से पेंशनभोगियों को 'जीवन नरिवाह में सुगमता' का अधिकार सुनिश्चति करने का कार्म कयि गया है। वस्तुतः इसकी सहायता से पेंशनभोगियों को अपनी शकियातों के नविरण के लयि बाधा मुक्त प्रशासनकि प्रणाली सुलभ कराए जाने का प्रयास कयि गया है।

उद्देश्य

- पेंशन अदालतों को वभिनिन मामलों जैसे - असंतुष्ट पेंशनभोगी, संबंधति वभिण, बैंक या CGHS (Central Government Health Scheme) प्रतनिधि, अर्थात् जहाँ भी प्रासंगिक हो, को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से शुरु कयि गया है, ताकि संबंधति मामलों का मौजूदा नयिओं के भीतर नपिटारा कयि जा सके।
- पेंशन अदालत के अलावा, अगले 6 महीनों में सेवानवृत्त होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पूर्व-सेवानवृत्तपरामर्श (Pre-Retirement Counselling - PRC) प्रदान करने का कार्म भी कयि जाता है।
- PRC कार्मशाला का उद्देश्य न केवल सेवानवृत्तों के बाद कर्मचारियों में उनके अधिकारों के प्रतजागरूकता पैदा करना है, बल्कि उन्हें चकितिसा सुवधाओं और स्वैच्छकि गतविधियों में भागीदारी सहति अग्रमि योजना के वषिय में शकिषति करना भी है।

सी-डैक सूचना मीडिया सर्वर (C-DAC Information Media Server)

- इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय ने सुशासन के लयि सी-डैक सूचना मीडिया सर्वर (CIMS) लॉन्च कयि है।
- सी-डैक सूचना मीडिया सर्वर (CIMS) एक कंप्यूटर उपकरण है जिसमें मांग के आधार पर ऑडियो और वीडियो उपलब्ध कराने वाला वशिष एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है।
- कम लागत वाली यह कफियाती प्रणाली शक्तिशाली और ऊर्जा कुशल मल्टीकोर प्रोसेसर वाले सगिल बोर्ड कंप्यूटर के साथ तैयार की गई है।
- इसे कसि वशिष इंटरनेट सेवा प्रदाता या डेटा कनेक्टविटी की आवश्यकता नहीं है। इसमें ऑफलाइन रहने की स्थिति में वीडियो देखने या डाउनलोड करने के लयि टेकस्ट प्रदर्शति करने, तस्वीरें देखने, वीडियो स्ट्रीमिंग, ई-ब्रोशर जैसी सामान्य वशिषताओं को शामिल कयि गया है।
- CIMS को स्थापति करना काफी सरल है, इसे संसद, (मौजूदा राज्यसभा, सदस्यों के वविरण), शकिषण संस्थानों (ई-बुकस, समय सारणि, दनि की खबरों, सूचनाओं), रेलवे स्टेशनों (ट्रेन चलने की जानकारी, स्टेशन लेआउट मैपिंग), अस्पतालों (ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर, रोगियों के रकिर्ड) जैसी जगहों पर आसानी से संचालति कयि जा सकता है।
- कोई भी उपयोगकर्ता कसि भी स्मार्ट डवाइस के माध्यम से वाई-फाई के साथ कनेक्ट हो सकता है और उपलब्ध जानकारी को मुफ्त में प्राप्त कर सकता है।

परविरतनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र (Variable Energy Cyclotron Centre)

- कैंसर देखभाल में नैदानिक और चकितिसकीय उपयोग हेतु साइक्लोट्रॉन का उपयोग रेडियोआइसोटोप का उत्पादन करने के लयि कयि जाता है।
- साइक्लोट्रॉन -30, भारत का सबसे बड़ा साइक्लोट्रॉन है। जैसे ही 30 एमवी बीम पहली बार फैराडे कप (Faraday Cup) तक पहुँचने में सक्षम होगा, उसी के साथ यह इस माह (सतिंबर) से परचालति हो गया।
- इसके बाद इस केंद्र के माध्यम से बीम का उपयोग 18 एफ (फ्लूराइन -18 आइसोटोप) के उत्पादन के लयि कयि गया।
- आपकी जानकारी के लयि बता दें कि 18 FIFluorodeoxyglucose (FDG), बीआरआईटी (Board of Radiation & Isotope Technology -

BRIT) द्वारा उपयोग किये जाने वाला एक रेडियो-फार्मास्यूटिकल है।

- यह केंद्र सहायक परमाणु प्रणालियों और नियामक मंजूरी प्राप्त होने के बाद अगले वर्ष के मध्य तक नियमिit रूप से उत्पादन कार्य शुरू कर देगा।
- VECC, कोलकाता में स्थित साइक्लोन -30 परमाणु ऊर्जा विभाग (Department of Atomic Energy - DAE) की एक इकाई है, इसके अंतर्गत बहुत-सी अद्वितीय विशेषताएँ नहिति हैं।
- Cyclone-30 (commissioning re-emphasises the capability of Indian scientists and engineers to deliver at the highest level of science and technology) यह केंद्र देश भर के लिये और विशेष रूप से पूर्वी भारत के लिये कफियती रेडियो आइसोटोप और संबंधित रेडियो फार्मास्यूटिकलस उपलब्ध कराएगा।
- इसके साथ-साथ यह जर्मनियम-68/गैलियम-68 जनरेटर के लिये स्व:स्थाने (in-situ) पैलेडियम-103 एवं गैलियम-68 आइसोटोप की उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि करेगा।
- इन आइसोटोपस का इस्तेमाल स्तन कैंसर के नदिान और पौरुष ग्रंथि कैंसर (prostate cancer) के उपचार के लिये कयिा जाता है।
- साइक्लोन -30 के परिचालन से जहाँ एक ओर भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की क्षमता में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर, देश को वज्ज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्चतम स्तर पर पहुँचने में भी सहायता मिलेगी।

ई-सहज पोर्टल

देश के कुछ विशेष संवेदनशील क्षेत्रों में कारोबार शुरू करने से पहले सुरक्षा संबंधी मंजूरी को आसान करने के लिये सरकार ने 'ई-सहज' नामक एक पोर्टल शुरू कयिा है।

- इससे सुरक्षा मंजूरी की प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा तेज़ी आएगी।
- कुछ विशेष संवेदनशील क्षेत्रों में कंपनियों, बोलीदाताओं और व्यक्तियों को लाइसेंस/परमिट/मंजूरी/कॉन्ट्रैक्ट आदि देने से पहले सुरक्षा संबंधी मंजूरीयें प्रदान करने हेतु गृह मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय है।

उद्देश्य

- राष्ट्रीय सुरक्षा मंजूरी का उद्देश्य आर्थिक खतरों सहित संभावित सुरक्षा खतरों का मूल्यांकन करना और प्रमुख क्षेत्रों में निवेश और परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी देने से पहले जोखिम का मूल्यांकन प्रदान करना है।
- इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं को पूरा करना और व्यापार में आसानी लाने तथा देश में निवेश को बढ़ावा देने के बीच स्वस्थ संतुलन स्थापित करना है।